



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 अक्टूबर, 2024

आश्विन 16, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 7/2024/1910/36-3-2024-01(सा०)-13-371018

लखनऊ, 8 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

सा०पी०नि०-28

चूंकि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद (अराजपत्रित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2024 को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसे अधिसूचना संख्या 278/36-3-2024-01(सा०)-13, दिनांक 6 फरवरी, 2024 द्वारा गजट में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिवसों की अवधि के अवसान को या पूर्व उससे संभाव्यतः प्रभावित समस्त व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और, चूंकि, पैंतालीस दिवस की उक्त अवधि के अवसान से पूर्व उससे संभाव्यतः प्रभावित व्यक्तियों से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद (अराजपत्रित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2024

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद (अराजपत्रित) कर्मचारी सेवा संक्षिप्त नाम नियमावली, 2024 कही जायेगी। और प्रारंभ

(2) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद (अराजपत्रित) कर्मचारी सेवा एक अधीनस्थ सेवा की कर्मचारी सेवा है जिसमें समूह "ग" का पद सम्मिलित हैं। प्रास्थिति

परिभाषाएं

3—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,—
 (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य श्रम कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है;
 (ख) "परिषद" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद से है;
 (ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
 (घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
 (ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
 (च) "श्रम कल्याण आयुक्त" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 8 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है;
 (छ) "सेवा के सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
 (ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
 (झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के अन्यथा आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है:

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या परिषद उसे आस्थगित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। सरकार समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

भर्ती का स्रोत समूह "ग"

5—सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:—

क्र0सं0	पदनाम	भर्ती का स्रोत/अर्हता
1	सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती/सरकार द्वारा विहित अर्हतानुसार।
2	लेखाकार	पदोन्नति/सरकार द्वारा विहित अर्हतानुसार।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के अधिनियमों, नियमों और आदेशों के अनुसार होगा।

राष्ट्रीयता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या
 (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
 (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी— ऐसा अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—सेवा में सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए:—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से लेखा कर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा।

9—अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने; अधिमानी अर्हताएं

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10—सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने आयु उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें भर्ती की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का ऐसा चरित्र होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा। चरित्र

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—ऐसा कोई व्यक्ति, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा—

(क) जिसने जीवित पति या पत्नी वाले व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, या वैवाहिक प्रास्थिति

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका-खंड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कोई चिकित्सीय प्रमाण-पत्र या स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें: शारीरिक स्वस्थता

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरे जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा। रिक्तियों का अवधारण

भर्ती और
पदोन्नति हेतु
प्रक्रिया

15-(1) नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित करेगा।

(2) लेखाकार के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) श्रम कल्याण आयुक्त-अध्यक्ष

(ख) अपर/उप श्रम कल्याण आयुक्त-सदस्य

(ग) श्रम आयुक्त कार्यालय के द्वितीय श्रेणी अधिकारी के रैंक से अनिम्न, अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी-सदस्य

(घ) श्रम आयुक्त कार्यालय के द्वितीय श्रेणी अधिकारी के रैंक से अनिम्न, अन्य पिछड़ी जाति का कोई अधिकारी-सदस्य

(3) पदोन्नति समिति मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करेगी।

वेतनमान

16-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न या अस्थायी रूप में हो, ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय के वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं-

	वेतन बैंड का नाम	वेतनमान
1	2	3
1	सहायक लेखाकार	वेतन-मैट्रिक्स लेवल-5 (29,200-92,300)
2	लेखाकार	वेतन-मैट्रिक्स लेवल-6 (35,400-1,12,400)

परिवीक्षा अवधि
में वेतन

17-मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी पहली वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

परिवीक्षा

18-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि,-

(क) उसके कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

20—सेवा में, किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

21—सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं पक्ष समर्थन सिफारिशों, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

22—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

23—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी भी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह मामले से न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है: सेवा की शर्तों में शिथिलता

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त या उसे शिथिल किये जाने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।

24—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर व्यावृत्ति नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट “क”

अनुसूची 1

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अराजपत्रित पदों का विवरण

संवर्ग	पद	पदों की संख्या
वर्ग	लेखाकार	01
	सहायक लेखाकार	01

परिशिष्ट “ख”

अनुसूची 2

सं०	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	लेखाकार	श्रम कल्याण आयुक्त	परिषद का अध्यक्ष
2	सहायक लेखाकार	श्रम कल्याण आयुक्त	परिषद का अध्यक्ष

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2024/1910/XXXVI-3-2024-01(Sa)-13-371018, dated October 8, 2024:

No. 7/2024/1910/XXXVI-3-2024-01(Sa)-13-371018

Dated Lucknow, October 8, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Labour Welfare Board (Non-Gazetted) Employees Service Rules, 2024 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 25 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (U.P. Act no. XIV of 1965) was published *vide* notification no. 278/36-03-2024-01(Sa)/13 dated February 6, 2024 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the *Gazette*;

AND, WHEREAS, no objections or suggestions were received from persons likely to be affected thereby, before the expiry of the said period of forty-five days;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers under sub-section (1) of section 25 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (U.P. Act no. XIV of 1965) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

The Uttar Pradesh Labour Welfare Board (Non-Gazetted) Employees Service Rules, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Labour Welfare Board (Non-Gazetted) Employees Service Rules 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official *Gazette*.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Labour Welfare Board (Non-Gazetted) Employees Service is a subordinate staff service which includes Group "C" posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
 - (a) "Appointing Authority" means the Labour Welfare Commissioner, Uttar Pradesh;
 - (b) "Board" means the Uttar Pradesh Labour Welfare Board constituted under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (U.P. Act no. XIV of 1965) ;
 - (c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;
 - (d) "Constitution" means the Constitution of India ;
 - (e) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;
 - (f) "Labour Welfare Commissioner" means the authority appointed under section 8 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (U.P. Act no. XIV of 1965) ;
 - (g) "Member of the Service" means a person substantially appointed under these rules or the rules or orders in force before the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service ;
 - (h) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;
 - (i) "Year of recruitment" means a period of Twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and the number of posts of each category in it shall be such as may be determined from time to time by the Government.
- (2) The strength of the Service and the strength of each category of posts therein, unless otherwise ordered under rule (1) to vary the same, are given in Appendix "A" :

Provided that the appointing authority may leave any post unfilled or the Board may hold it in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation. The Government may from time to time create such additional permanent or temporary posts as it deems fit.

5. Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

Source of Recruitment Group "C"

Sl. No.	Designation	Source of Recruitment/ Qualification
1	Assistant Accountant	Direct Recruitment/As per the qualification prescribed by the Government.
2	Accountant	Promotion/As per the qualification prescribed by the Government.

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the Acts, rules and orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Reservation

7. A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be :-

Nationality

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and The United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Accountant in the Service must possess the following qualifications :-

Academic qualification

(i) Bachelor's Degree in Commerce from a University established by law in India or a Post Graduate Diploma in Accountancy from a University or Institute recognised by the Government.

(ii) 'O' level Diploma in computer operation from an Institute recognised by the Government.

9. A candidate who :-

Preferential qualification

(i) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) has obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Accountant must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which recruitment is to be made :

Age

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Character

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status	<p>12. No person:-</p> <p>(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or</p> <p>(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service :</p> <p>Provided that the Government may if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.</p>												
Physical fitness	<p>13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate or fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book Volume II, Part III :</p> <p>Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.</p>												
Determination of vacancies	<p>14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.</p>												
Procedure for Recruitment and Promotion	<p>15. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.</p> <p>(2) For the purpose of promotion on the post of Accountant a Committee shall be constituted comprising:-</p> <p>(a) Labour Welfare Commissioner - Chairman.</p> <p>(b) Additional/ Deputy Labour Welfare Commissioner -Member.</p> <p>(c) Any officer belonging to Scheduled Caste not below the rank of class II officer of Labour Commissioner Office-Member.</p> <p>(d) Any officer belonging to Other Backward Caste not below the rank of class II officer of Labour Commissioner Office-Member.</p> <p>(3) Promotion committee will consider the promotion for the post of Accountant from amongst substantively appointed Assistant Accountant who have completed three Years service as such on the first day of the year of recruitment.</p>												
Scale of Pay	<p>16. (1) The scales of pay admissible to person appointed to the various categories of post in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.</p> <p>(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given as follows:-</p> <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Name of Pay Band</th><th>Pay Scale</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>Assistant Accountant</td><td>Pay Matrics level-5 (29,200-92,300)</td></tr><tr><td>2</td><td>Accountant</td><td>Pay Matrics level-6 (35,400-1,12,400)</td></tr></table>	Sl. No.	Name of Pay Band	Pay Scale	1	2	3	1	Assistant Accountant	Pay Matrics level-5 (29,200-92,300)	2	Accountant	Pay Matrics level-6 (35,400-1,12,400)
Sl. No.	Name of Pay Band	Pay Scale											
1	2	3											
1	Assistant Accountant	Pay Matrics level-5 (29,200-92,300)											
2	Accountant	Pay Matrics level-6 (35,400-1,12,400)											
Pay during Probation	<p>17. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :</p> <p>Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.</p>												

18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013. Probation
- (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that the probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
- (4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
19. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if:- Confirmation
- (a) his work and conduct should be described as satisfactory;
- (b) his integrity be certified ;
- (c) The appointing authority is satisfied that he is otherwise suitable for confirmation.
20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the Service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. Seniority
21. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. Canvassing
22. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. Regulation of other matters
23. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner : Relaxation from the conditions of service
- Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.
24. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard. Saving

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

Appendix "A"

Schedule-1

Details of Non-Gazetted posts of the Uttar Pradesh Labour Welfare Board

Cadre	Post	Number of post
Category	Accountant	01
	Assistant Accountant	01

Appendix "B"

Schedule-2

No.	Designation	Appointing authority	Appellate authority
1	Accountant	Labour Welfare Commissioner	Chairman of the Board
2	Assistant Accountant	Labour Welfare Commissioner	Chairman of the Board

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 287 राजपत्र-2024-(737)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 10 सा0 श्रम-2024-(738)-50+50=100 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।